S. No.	Recommendation	Action taken
3	Retirement age of the seamen is to be reduced to 58 years from the present 60 years	Orders have been issued that the reduced retirement age would be applicable to seamen who are registered on or after 1-7-1982.
4	A scheme for financial assistance to the unemployed seamen be worked out and implemented.	This has been discussed in detail at various meetings of shipowners and seafarers but no acceptable scheme has yet been finalised. Ship-owners have expressed their inability to make funds available in the present state of recession.
5	Issue of Continuous Discharge Certificates to be confined to the Shipping Masters at Bombay and Calcutta only.	Orders have been issued restricting the issue of CDCs to Bombay and Calcutta.
6	Pre-entry medical standards for seamen to be reviewed.	After consultation with Ministry of Defence, it is felt that existing medical standards are adequate.
7	Pre-entry educational qualification to be raised to standard X (pass) from standard VIII (pass).	Since pre-sea training has been suspended now, the revised educational standards will be decided at the time of next advertisement for intake of trainees.

Second Hooghly Bridge

1725. SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) what amount has so far been allocated by the Central Government for the second Hooghly Bridge and what amount has been paid to the State Government and in how many instalments; and

(b) what are the reasons for non payment of allocated money in lump sum to facilitate smooth planning and construction?

THE MINISTER OF TRANSPORT (SHRI BANSI LAL (a) Second Hooghly Bridge being constructed at Calcutta, would fall on a State Highway and, therefore, the Government of West Bengal are primarily concerned with the Project, as constitutionally the roads declared as National Highways only are the responsibility of the Government of India. However, the Government of India have agreed to provide loan assistance of Rs. 150 crores to the West Bengal Government as a special case. Funds are released every year *on* the basis of the acrual requirements projected by the State Government from time to time An amount of Rs. 104.12 crores has, so far been released.

(b) Does not arise.

Transportation of betel-leaves

1726. SHRI NEPALDEV BHATTACHARJEE: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) what arrangements Railways have made to facilitate speedy bookings for transportation of betel-leaves:

(b) which are the main Railway stations which handle loading and unloading of betel-leaves; and

(c) what is the amount the Railways earn on bookings and transportation of betel-leaves on an average?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Betel-leaves as and when offered are accepted for booking and are despatched by brake vans of first available Mail/ Express or Sectional passenger trains. To further regulate the loading of this traffic, specific quotas have been earmarked for certain stations fox loading by certain trains.

(b) The names of the main loading and unloading Railway Stations handling betel-leaf traffic, Railway wise, have been shown in the statement attached. *[See* Appendix CXXVI, Annexure No. 30]

(c) Commodity-wise earnings for all the commodities are not maintained and betel leaf commodity is one of such commodities for which no separate figures of earnings are available.

चुंगी कर का समाप्त किया जाना

1727. श्री शकर सिंह वाघेला : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन विकास परिषद ने अप्रैल, 1982 में यह सुझाव दिया था कि चुंगीकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यदि हां, तो किन किन राज्यो और संघ शासित क्षेत्रो ने अब तक यह समाप्त नहीं किया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से बातचीत की है यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) माल परिवहन के बेहतर अंतर-राज्य आवागमन को सरल बनाने के लिये परिवहन विकास परिषद ने मानदंडों के भाग के रूप में राज्यों को चुंगी हटाने की सिफारिश की है और अपनी बैठकों में इसकी स्थिति की समीक्षा करती है। लेकिन पंजाब हरियाणा जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली गोवा दमन और दीव अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा पांडेचेरी संघ राज्य शासित क्षेत्रों ने आज भी चुंगी प्रणाली समाप्त नहीं की है। चुंगी हटाये जाने से स्थानीय निकायो को राजस्व की हानि होगी इसलिये एक सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिये विक्रय कर पर या मोटर यान करों पर प्रभार की लेवी लगाने आदि जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर सकते हैं।

देश में निरक्षरता

1728. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री कैलाश पति मिश्र :
श्री अश्विनी कुमार :
श्री रामकृष्ण मजुमदार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर 1985 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि "चेलेंज आफ एजुकेशन" नामक पत्र के अनुसार भारत में सन् 2000 तक निरक्षरों की संख्या लगभग पचास करोड होने जा रहीं है और विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार 20वीं शताब्दी के अन्त तक विश्व भर के 15 से 19 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के कुल निरक्षरों में से 54 प्रतिशत निरक्षर अकेले भारत में होंगे ; और

(ख) इक्कीसवीं शताब्दी में प्रवेश के समय विश्व के निरक्षरों की कुल संख्या की तुलना में भारत में अधिक निरक्षर व्यक्तियों के होने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं ?

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) देश के समस्त उत्पादक कार्य बल तथा पुनरुत्पादक आयु वर्ग में सतत निरक्षरता से राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नये बीस सूत्री कार्यक्रम में इन कार्यक्रमों को शामिल करते हुए गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी है। निर्धारित किये गये लक्ष्य हैं : प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना तथा वर्ष 1990 तक 15—35 आयु वर्ग में